

इन केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी 549 महत्वपूर्ण जैनेरिक दवाइयां, अस्पताल परिसर व स्थान मुहैया कराने के लिए राज्यों से बातचीत तीन हजार जन औषधि भंडार खोलनी सरकार

भारत

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

लोगों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नई जन औषधि भंडार योजना शुरू करेगी। इसके तहत देश भर में तीन हजार जन औषधि भंडार खोले जाएंगे।

इन केंद्रों पर सस्ते दवाओं में जैनेरिक दवाएं मिलेंगी। देश में जैनेरिक दवाओं की मांग है। लेकिन अभी तक सिर्फ

राज्यों को ले रहे भरोसे में

केंद्र जन औषधि भंडारों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से बात कर रहा है, ताकि वे अपने अस्पताल परिसरों में इन भंडारों की स्थापना के लिए स्थान उपलब्ध कराएं। बाकी का कार्य केंद्र सरकार खुद करेगी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों के अस्पतालों में पहले से जन औषधि भंडार चल रहे हैं, उनके बेहद प्रभावी नतीजे रहे हैं।

98 जन औषधि भंडार ही देश में खुल पाए हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि हम मौजूदा योजना में बदलाव कर रहे हैं। अबल कुछ महीनों में नई योजना की शुरुआत करेंगे। देश के सभी बड़े अस्पतालों से लेकर जिला अस्पतालों

तक में जन औषधि भंडार खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर लोगों को जैनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे दवाओं पर मरीजों का खर्च आधे से भी कम रह जाएगा। औषधि विभाग के सचिव डॉ. बी. के. सुब्बाराज ने बताया कि इन केंद्रों

पर आम इस्तेमाल की 549 जैनेरिक दवाएं उपलब्ध रहेंगी। आमतौर पर इन दवाओं से करीब-करीब सभी आम प्रचलित बीमारियों का इलाज हो सकता है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए फार्मास्यूटिकल ब्यूरो को मजबूत किया जा रहा है। यह ब्यूरो देश भर में जन औषधि भंडारों की स्थापना एवं संचालन का कार्य देखेगा। ब्यूरो में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। उसे आवश्यक स्टाफ भी मुहैया कराया जाएगा।

क्या है जैनेरिक दवाएं

जैनेरिक दवा वह दवा है जो बिना किसी पेटेंट के बनाई और बेची जाती है। जैनेरिक दवा के फार्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है किंतु उसके सक्रिय घटक पर पेटेंट नहीं होता। जैनेरिक दवाइयां गुणवत्ता में किसी भी प्रकार बांडेज दवाइयों से कम नहीं होती और उतनी ही असरकारी भी होती हैं। इसलिए इनके दाम कम होते हैं। सरकारी अस्पतालों, सीजीएचएस आदि सेवाओं में बड़े पैमाने पर जैनेरिक दवाओं की खरीद होती है। लेकिन आम लोगों तक इन दवाओं को पहुंचाने के लिए सरकार कोई ठोस तंत्र अभी तक खड़ा नहीं कर पाई है।